लूटकी खुली छूट

सर्वोच्च न्यायालयने कैंसरकी दवाओंपर भारी मुनाफेकी खुली लूटपर कड़ी टिप्पणी करते हुए एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर पूरा तंत्र दवा निर्माता कम्पनियोंकी क्यों मदद कर रहा है? कैंसरकी दवाओंपर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और रिटेल विक्रेताओंको मिलने वाली कीमत (रिटेलर प्राइस) में भारी अन्तरपर मंगलवारको न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहताकी पीठने जो कड़ी टिप्पणी है वह सरकार और दवा निर्माता कम्पनियोंको कड़ा सन्देश भी है। पीठका यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि दवाओंके मूल्य निर्धारणमें इतना बड़ा अन्तर होनेके बाद भी पूरा तंत्र दवा निर्माताओंकी सहायतामें क्यों सक्रिय है? यह लूटकी खुली छूट जैसा है। साथ ही यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि क्या निर्माताओंको मनमानी करनेकी छूट दी जानी चाहिए? यह मुद्दा आम नागरिकों और गरीब मरीजोंसे जुड़ा है। यह केवल व्यापारका मामला नहीं है। पीठने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की भूमिकाको भी कटघरेमें खड़ा कर दिया है और कहा है कि एनपीपीए पूरी तरहसे निष्क्रिय निकाय लगता है। पीठका यह भी कहना है कि ११ हजार रुपयेमें मिलने वाला कीमोथैरिपीका इंजेक्शन एक लाख ३० हजार रुपयेमें कैसे बेचा जा रहा है और मूल्योंके बीच भारी अन्तरका धन कहां जा रहा है? वस्तुत: सर्वोच्च न्यायालयकी कड़ी टिप्पणीको केवल दवा निर्माता कम्पनियों या निजी अस्पतालोंकी आलोचनाके रूपमें देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह मामला भारतकी स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजोंके अधिकारसे सीधे जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालयने दवाओंकी खरीद और बिक्री मूल्योंमें इस भारी अन्तरको अत्यन्त गम्भीर माना है और कहा है कि मरीजोंको इस प्रकारकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? सर्वोच्च न्यायालयकी चिन्ता केवल यह नहीं है कि कोई कम्पनी अधिक मुआवजा कमा रही है। मूल प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओंके बाजारमें मरीजकी मजबूरीका फायदा उठाया जा सकता है? कैंसर जैसी बीमारीमें मरीज और परिवारके पास दवा खरीदनेके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है और वह कीमतपर मोलभाव करनेकी स्थितिमें भी नहीं होता है। ऐसेमें बाजारकी सामान्य मांग-आपूर्ति वाली अवधारणा कमजोर पड़ जाती है। इस पूरे प्रकरणमें अलग-अलग स्तरपर शुल्क लिया जा रहा है। अस्पताल और डाक्टरोंकी मनमानी कमाई और उपहार तथा अन्य सुविधाएं देनेकी संस्कृतिसे भी दवाओंके मूल्य बढ़ जा रहे हैं। इसे कैसे रोका जाय इसपर सरकारको सोचना होगा। निगरानी तंत्रको भी मजबूत करना होगा तभी मूल्योंमें कमी आ सकती है।

वायु प्रदूषणका दंश

वायु प्रदूषण पृथ्वीके जीवधारियोंके अस्तित्वके लिए बड़े खतरेका संकेत हैं। इसे नियंत्रित करनेके लिए वैश्विक मंचोंसे बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती हैं और इसके निदानके लिए रास्ते भी सुझाये जाते हैं लेकिन यह महज कागजोंतक सिमटकर रह जाता है। कोई भी देश इस समस्याको गम्भीरतासे नहीं लेता। यह गम्भीर चिन्ताका विषय है। भारतके शहरोंको स्वच्छ हवा देनेके लिए पिछले सात सालोंमें १२ हजार करोड़ रुपयेसे अधिक खर्च किये गये, इसके बावजूद देशके ९० प्रतिशत शहरोंमें प्रदूषणका स्तर निर्धारित मानकके अनुरूप नहीं हो सका। दिल्लीकी स्थिति सर्वाधिक चिन्ताजनक है। आंकड़ोंपर गौर करें तो वर्ष २०१६ से २०२५ तक राजधानीका वार्षिक औसत स्तर किसी भी साल राष्ट्रीय मानकोंके अनुरूप नहीं रहा। सेण्टर फार रिसर्च आन एनर्जी एण्ड क्लीन एयरके स्वतंत्र विश्लेषणके अनुसार जनवरी २०१९ में शुरू किये गये इस कार्यक्रममें सात साल बाद भी प्रदूषण नियंत्रणकी तस्वीर सन्तोषजनक नहीं है। खास बात यह है कि प्रदूषित हवाका दुष्प्रभाव जीवधारियोंपर तो पड़ ही रहा है, कृषि उत्पादपर भी इसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है जो देशके विकास और अर्थव्यवस्थाके लिए शुभ संकेत नहीं है। हवा क्यों प्रदूषित हो रही है, इसके कारण और निवारणके बारेमें सोचना और इसके लिए सख्त कदम उठाना होगा। प्रदूषणपर आक्सफैमकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसके अनुसार दुनियाके सबसे अमीर करीब ८० लाख लोग न केवल प्रदूषण फैलानेमें आगे हैं, बल्कि इससे होने वाली प्राकृतिक आपदाओंसे दोहरा मुनाफा कमानेमें भी आगे हैं। ये धनकुबेर दुनियाकी सबसे गरीब ३५० करोड़ आबादीके मुकाबले ज्यादा कार्बन प्रदूषण फैलाते हैं। इन बेहद अमीर लोगोंका ऐसे कारोबारमें भारी निवेश है, जो पर्यावरणको नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपदाओंसे राहत, बचाव, मरम्मत और पुनर्निर्माणसे जुड़े कारोबारमें भारी निवेश कर दो गुना मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे लोगोंपर अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर दबाव बनानेकी जरूरत है, तभी वायुकी गुणवत्ता सुधारी जा सकती है।

लोक संवाद

पर्यावरण का संरक्षण जरूरी

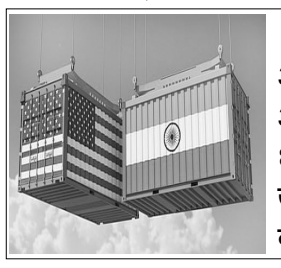
महोदय,-दुनिया आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषणकी गम्भीर चुनौतीका सामना कर रही है। पर्यावरण संरक्षणकी जिम्मेदारी पूरी मानवता की है, लेकिन प्रदूषणके मुद्देपर विकासशील देशोंको अक्सर कठघरेमें खड़ा किया जाता है। विकसित देश भूल जाते हैं कि उन्होंने दशकोंतक संसाधनोंका अधिकतम दोहन कर मजबूत आर्थिक ढांचा खड़ा किया है, जिसकी पर्यावरणीय कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। यदि प्रदूषणकी जिम्मेदारी तय करनी है तो ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको भी ध्यानमें रखना होगा। कार्बन टैक्स और पर्यावरण संबंधी प्रतिबंधोंके नामपर विकासशील देशोंके विकासको बाधित करना न्यायसंगत नहीं है। पर्यावरण संरक्षण व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका हथियार नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोगका माध्यम होना चाहिए। विकसित देशोंको अपना फर्ज समझना होगा। **-महेश कुमार, वाया ईमेल।**

व्यापार समझौतेकी सम्भावना

हालमें ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पने कहा कि भारत और अमेरिका एक नये व्यापार समझौतेको अंतिम रूप देनेके बेहद करीब हैं। डोनाल्ड ट्रम्पने स्पष्ट किया कि दोनों देश समझौता करनेके इच्छुक हैं और यह नया सौदा पिछले सभी द्विपक्षीय समझौतोंसे काफी अलग होगा।

❐ डा. जयंतीलाल भंडारी

हालमें ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरेपर आये। मार्कोने २० से २२ अक्तूबरके बीच भारत दौरेके दौरान भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर और अन्य शीर्ष नेताओंके साथ व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा सहयोगके मुद्दोंपर विस्तृत चर्चा की। रुबियोने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के जामनगर संयंत्रका दौरा किया और भारतकी इस अनूठी रिफायनिंग क्षमताकी सराहना की। रुबियोने यह भी कहा कि भारत-अमेरिकी व्यापार वार्ता अब अंतिम और तकनीकी स्तरपर पहुंच चुकी है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकोंमें वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक मानचित्रपर भारत और अमेरिकाके संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदारीके रूपमें उभरे थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्यमें ये संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी नयी आर्थिक नीतियों, संरक्षणवादी दृष्टिकोण और सख्त टैरिफ रणनीतिके कारण एक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील मोड़पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज भारतके समक्ष एक तरफ अमेरिकी बाजारमें अपने मजबूत निर्यातको सुरक्षित रखनेकी चुनौती है तो दूसरी तरफ रूससे रियायती दरोंपर अपनी ऊर्जा जरूरतोंकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनेका रणनीतिक संतुलन साधनेका दबाव है।



भारत और अमेरिकाके बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौतेकी वार्ताके तहत भारतको सहयोग और व्यापारिक प्रतिस्पर्धाके बीच एक संतुलित और दृढ़ रुख अपनाना होगा। भारतको कृषि, डेयरी और एमएसएमई जैसे संवेदनशील क्षेत्रोंमें राष्ट्रीय हितोंकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि इन क्षेत्रोंसे भारतकी विशाल आबादीकी आजीविका जुड़ी हुई है। इसके साथ ही औषधियों, वस्त्र, हस्तशिल्प और जेम्स एंड ज्वेलरीपर टैरिफ दरोंको शून्य या न्यूनतम स्तरपर लानेके लिए भारतको कड़ा मोलभाव करना होगा, ताकि भारतीय निर्यातकोंको अमेरिकी बाजारमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता रहे।

इस खींचतानके बीच हालिया अमेरिकी नीतिगत फैसले, वीजा नियमोंमें अत्यधिक सख्ती, जेनेरिक दवाओंपर प्रस्तावित शुल्ककी चुनौतियोंके बावजूद अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्रम्प और विदेश मंत्री रुबियोकी हालिया सकारात्मक टिप्पणियोंसे भारत और अमेरिकाके बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) एक नयी पटकथाके साथ उभरते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि १९९१ के आर्थिक उदारीकरणके बादसे लेकर २०१६ तक भारत और अमेरिकाके बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधोंमें एक प्रभावी दौर देखनेको मिला। वर्ष २००० में दोनों देशोंके बीच वस्तुओं एवं सेवाओंका द्विपक्षीय व्यापार लगभग छह गुना बढ़कर अभूतपूर्व स्तरपर पहुंच गया। इस दौरान अमेरिकी बाजारमें भारतीय आईटी सेवाओं, फार्मास्युटिकल उत्पादों, कपड़ों और रत्नोंकी मांगमें जबरदस्त इजाफा हुआ, जिससे भारतकी आर्थिक साख वैश्विक स्तरपर स्थापित हुई। इस आर्थिक प्रगतिको २००८ के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते और २०१६ में भारतको मिले मेजर डिफेंस पार्टनरके दर्जेसे गहरा रणनीतिक बल मिला। रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकियोंके हस्तांतरणके नये द्वार खुलनेके साथ-साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कम्पनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रोने अमेरिकी अर्थव्यवस्थामें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान एच१बी वीजा नीतिने भारतीय कुशल पेशेवरोंको अमेरिकामें कार्य करने और वैश्विक पहचान बनानेके पर्याप्त अवसर प्रदान किये। निवेशके दृष्टिकोणसे भी यह दौर बेहद समृद्ध रहा, जहां २००० से २०१६ के बीच माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जीई, आईबीएम और बोइंग जैसी शीर्ष अमेरिकी कम्पनियोंने भारतके तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्रोंमें भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किया। साथ ही भारतीय कम्पनियोंने भी अमेरिकी बाजारमें अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। ट्रम्प कालमें शुरू हुई संरक्षणवादी नीतियों, टैरिफ और वीजा पाबंदियोंसे ठीक पहलेतक दोनों देशोंके आर्थिक रिश्ते मुक्त और रणनीतिक सहयोगकी मजबूत नींवपर लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसेमें अब अमेरिकासे व्यापार समझौतेकी संभावनाओंका सुकूनदेह परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। हालमें १७ अक्तूबरको अमेरिकी प्रशासन द्वारा लींडसे ग्राहम अधिनियमके तहत रूसी तेल खरीददारोंपर सौ प्रतिशत टैरिफ लगानेके कठोर फैसलेको ६० दिनोंके लिए स्थगित करना भारतीय अर्थव्यवस्थाके लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। मध्य-पूर्वके तनाव और यूक्रेन-रूस संघर्षसे उपजे ऊर्जा संकटके बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियोने भारतकी ऊर्जा जरूरतों और स्रोतोंके विविधीकरणकी सराहना की है। रूससे प्रतिस्पर्धी दरोंपर कच्चा तेल खरीदनेकी इस छूटसे भारतमें ईंधनकी लागत नियंत्रित रहेगी और घरेलू बाजारमें महंगीका दबाव कम होगा। इसके साथ ही इस फैसलेने टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-गहन क्षेत्रोंके भारतीय निर्यातकों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अल्पकालिक अनिश्चिततासे बचाकर अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरोंका प्रवाह बनाये रखनेमें मदद की है। नि:संदेह तेल टैरिफपर ६० दिनोंकी राहतके बावजूद, आव्रजन और वीजा नियमोंमें सख्तीके कारण भारतीय आईटी पेशेवरों, कारपोरेट जगत और चिकित्सा विशेषज्ञोंपर संकट गहराता जा रहा है। एच१बी वीजापर लगाये गये एक लाख डालरके अतिरिक्त शुल्कको एक वर्षके लिए बढ़ाने और जांच प्रक्रियाको बेहद सख्त करनेसे बड़ी भारतीय आईटी कम्पनियोंके पंजीकरणमें ९२ प्रतिशतककी भारी गिरावट दर्ज की गयी है, जबकि कुल मंजूर एच१बी वीजामें भारतीयोंकी हिस्सेदारी लगभग ७१ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त नौकरी छूटनेके बाद मिलने वाले ६० दिनोंके वैधानिक ग्रेस पीरियडको खत्म करनेका नया प्रस्ताव भारतीय पेशेवरोंके लिए गम्भीर संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि नौकरी समाप्त होते ही उनका कानूनी गैर-आप्रवासी दर्जा खत्म हो जायगा और उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़कर पुन: आवेदन करनेकी बाध्यता होगी। ऐसेमें अमेरिकासे आर्थिक अनिश्चितता और संरक्षणवादके इस दौरमें भारतको केवल रक्षात्मक रुख अपनानेके बजाय अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितोंकी सुरक्षाके लिए एक दीर्घकालिक और बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। अमेरिका और यूरोपीय संघपर अत्यधिक निर्भरता कम करनेके लिए लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्वके गैर-पारम्परिक बाजारोंमें भारतीय उत्पादोंकी पैठ बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओंके साथ लंबित मुक्त व्यापार समझौतोंको तेजीसे अंतिम रूप देना होगा। घरेलू स्तरपर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओंका विस्तार करना होगा और सेवा क्षेत्रको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर तथा उच्च प्रौद्योगिकीकी दिशामें अपग्रेड करना होगा, ताकि अमेरिकी नीतियोंके झटकोंका प्रभाव न्यूनतम किया जा सके। भारत और अमेरिकाके बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौतेकी वार्ताके तहत भारतको सहयोग और व्यापारिक प्रतिस्पर्धाके बीच एक संतुलित और दृढ़ रुख अपनाना होगा। भारतको कृषि, डेयरी और एमएसएमई जैसे संवेदनशील क्षेत्रोंमें अपने राष्ट्रीय हितोंकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि इन क्षेत्रोंसे भारतकी विशाल आबादीकी आजीविका जुड़ी हुई है। इसके साथ ही औषधियों, वस्त्र, हस्तशिल्प और जेम्स एंड ज्वेलरीपर अमेरिकी टैरिफ दरोंको शून्य या न्यूनतम स्तरपर लानेके लिए भारतको कड़ा मोलभाव करना होगा, ताकि भारतीय निर्यातकोंको अमेरिकी बाजारमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता रहे। अंतत: अमेरिका द्वारा मिली ६० दिनोंकी यह राहत भले ही अस्थायी और अल्पकालिक हो, लेकिन यह भारतके लिए महज एक सांकेतिक छूट नहीं है। यह ६० दिनोंका समय भारतको नये सिरेसे संजोनेका एक प्रभावी अवसर प्रदान करता है।

सड़क से सत्ता पर आना चाहता है विपक्ष

❐ सुरेश रुंगटा

भारत का निर्वाचन आयोग वह संस्था है जो देश में चुनाव करवाती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची सही रहे। मतदाता सूची, उन नागरिकों की आधिकारिक सूची है, जिन्हें चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। मतदाता सूची में समय-समय पर गहन पुनरीक्षण और सुधार करना पड़ता है, ताकि योग्य मतदाताओं के नाम ही सूची में रह सके। इसके लिए मतदाता सूची में से मृत, स्थान बदल चुके या एक से ज्यादा जगह दर्ज लोगों के नाम हटाये जाने के साथ-साथ योग्य लोगों के नामों को जोड़ा जाता है। इसमें चुनाव अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठी करते हैं। इस पूरी प्रकिया को एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अर्थात् विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। २०२५-२६ में हो रहे एसआईआर से पहले भी देश में आठ बार एसआईआर हो चुके हैं।

भारत की विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव हारी है, उन राज्यों में हुए एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों के नाम काटे गये हैं, उन्हें गलत बताते हुए उसे जोड़ने तथा चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इसके लिए जिम्मेवार बताते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रही है साथ ही आगे से चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने के लिए आंदोलित है। कांग्रेस एसआईआर की आड़ में वोट चोरी को मुद्दा बनाकर देशवासियों को गुमराह करने का काम कर रही है। वास्तव में तो चुनाव आयोग पर अमर्यादित बयानबाजी और अनर्गल आरोप लगाकर कांग्रेस इस संवैधानिक संस्था को बदनाम और चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर चुनावी प्रकिया पर से लोगों के विश्वास को खत्म करना चाहती है। जबकि एसआईआर पूर्ण होने के बाद प्रारूप मतदाता सूची सार्वजनिक कर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही उपलब्ध करायी जाती है, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित अवधि में दावे प्रस्तुत किए जा सकें। केवल यह कहना कि नाम बड़ी संख्या में काटे गये, पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आरोप तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होने चाहिए। बिना पर्याप्त प्रमाण के पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, तनिक भी उचित नहीं है। आखिरकार लो. कतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने वाली संस्था की निष्पक्षता पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी, नागरिकों की जागरूकता और सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति तथ्यपरक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है।

बिहार में हुए एसआईआर के द्वारा हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बिहार में हुए एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने कई व्यवस्थाएं की थी। १ अगस्त २०२५ को बिहार की प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलोक्टोरल रोल) प्रकाशित की गई थी। जिसकी बूथवार प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही आम नागरिकों के लिए भी यह सूची निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध थी। १ अगस्त से १ सितंबर २०२५ तक मतदाताओं और राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। जिन पात्र मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं थे, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम जोड़वाने का दावा कर सकते थे। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। अब प्रश्न यह है कि प्रारूप सूची अंतिम सूची नहीं होती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि नागरिक, राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि सूची की जांच करें और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटा या किसी प्रविष्टि में कोई त्रुटि है तो निर्धारित समय के भीतर सुधार की मांग करें। इसलिए सूची में किसी का नाम नहीं होना, अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि उसका नाम जानबूझकर हटाया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगभग १३ करोड़ लोगों के नाम काटे जाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वे इस आंकड़े के साथ इसका विवरण लोगों से छुपा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों में ६.३ करोड़ प्रविष्टियां ऐसे मतदाताओं की है, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गये, ३.०१ करोड़ मतदाताओं का उनके पते पर कोई जानकारी नहीं मिली, २.८ करोड़ प्रविष्टियां मृत मतदाताओं की है और १.०२ करोड़ नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाये गये। एसआईआर होने से पहले विपक्षी पार्टियों द्वारा इसे करवाने की बार-बार मांग की जा रही थी और यह आरोप लगाया जाता था कि भाजपा के वोटर कई जगहों पर जाकर वोट देते हैं। अब जब एसआईआर करवाकर उनके नाम हटाने का काम चुनाव आयोग ने किया तब अब इस एसआईआर पर भी विपक्ष को आपत्ति है।

लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है। इसलिए मतदाता सूची की सफाई चुनावी निष्पक्षता की पहली शर्त है । लेकिन यह सफाई वर्षों टलती रही। पिछला गहन पुनरीक्षण २००२-०४ में हुआ था। बीच के २० से अधिक वर्षों में पलायन और शहरीकरण ने बस्तियों का नक्शा बदल दिया। आयोग का कहना है कि तेज शहरीकरण, पलायन, मृत्यु की सूचना न मिलने और डुप्लीकेट पंजीकरण से सूचियां अशुद्ध होती गईं। युवा मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों को जब देखते हैं तो ज्ञात होता है कि युवा मतदाताओं की संख्या बराबर बढ़ी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार २४ जून २०२५ के बाद १८ से २८ वर्ष के आयु वर्ग में २.३७ करोड़ नये मतदाता जोड़े गये, जबकि इस आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या १७.३८ करोड़ के लगभग है। यह तथ्य इस आरोप का एक ज्वलंत स्पष्टीकरण है कि एसआईआर के कारण नये मतदाताओं के पंजीकरण का रास्ता बंद नहीं हुआ था। नये जेन-जी मतदाताओं के जुड़ने का आंकड़ा हर महीने १६ लाख यानी प्रतिदिन लगभग ५० हजार के करीब हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार देशव्यापी एसआईआर के सभी निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से हुए हैं। लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन की व्यवस्था नहीं, बल्कि विचारों पर मंथन, संवैधानिक मर्यादाओं और जनमत के सम्मान से संचालित होने वाली जीवन-पद्धति है। इसकी वास्तविक शक्ति चुनावों में निहित है, जहां जनता अपने मताधिकारों के माध्यम से सरकारों का भाग्य निर्धारित करती है। किन्तु जब चुनावी राजनीति में पराजय का सामना करने वाले दल जनादेश पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, निर्वाचन प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा करें और जनता के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने के लिए झूठे नरेटिव गढ़े जाने लगे तो यह चिंता का विषय हो जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि देश की राजनीति कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही है?

आज भारत में चुनाव पारदर्शिता, कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां जहां-जहां चुनाव हारी, वहां-वहां चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में अनियमिताओं के कारण चुनाव चोरी हुई है। लेकिन जिन प्रांतों में उन्हें सफलता मिली, उस संबंध में वे कुछ भी नहीं बोलते। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है? जीत गये तो ठीक, अन्यथा ईवीएम खराब, तो कभी एसआईआर पर सवाल। यदि किसी राजनीतिक दल को लगता है कि चुनावों में धांधली हुई है, मतदाता सूची में गड़बड़ी है अथवा किसी नागरिक का नाम अनुचित ढंग से हटाया गया है, तो उसे प्रमाण के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। किसी भी अनियमितता की आशंका को बिना पर्याप्त साक्ष्य के चुनाव चोरी कहना कदापि उचित नहीं है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार जरूर है, लेकिन विरोध का उद्देश्य क्या है और उसकी भाषा कैसी है? यह विषय महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस का आंदोलन मतदाता सूची में सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और शिकायतों का निवारण है, तो उसे प्रमाणों के साथ अपनी मांग रखनी चाहिए। इसके विपरीत यदि राजनीतिक विमर्श में हर चुनावी परिणाम को संदेहास्पद बताने की प्रवृत्ति बढ़ती रही, तो इससे जनता के मन में चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा हो सकता है। यहां एक बुनियादी प्रश्न उठता है-क्या लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का रास्ता जनादेश से होकर गुजरना चाहिए या जनादेश देने वाली प्रक्रिया को ही अविश्वसनीय बताकर राजनीतिक वातावरण को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखना चाहिए। देशहित में देश के सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पर गहन विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का मार्ग जनता के मत से होकर गुजरता है, न कि सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन, संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास और जनभावनाओं को उकसा कर दबाव बनाने की राजनीति से। असहमति लोकतंत्र का प्राण है, लेकिन असहमति के नाम पर संवैधानिक मर्यादाओं को चुनौती देना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करेगा। यदि राजनीतिक दल जनादेश को स्वीकार करने के बजाए सड़कों की भीड़ को सत्ता प्राप्ति का विकल्प बनाने लगे, तो यह देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए शुभ नही होगा।

अखण्ड सौभाग्य प्रदाता चौथव्रतोत्सव

❐ रमेश सर्राफ धमोरा

भारत एक धर्म प्रधान देश हैं। यहां सालके सभी दिनोंका महत्व होता है तथा सालका हर दिन पवित्र माना जाता है। भारतमें करवा चौथ हिन्दुओंका एक प्रमुख त्योहार है। यह कार्तिक मासकी कृष्ण पक्षकी चतुर्थीको मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदयसे पहले करीब ४ बजेके बाद शुरू होकर रातमें चन्द्रमा दर्शनके बाद सम्पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियोंसे लेकर आधुनिक महिलाएं करवा चौथका व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साहके साथ रखती हैं। यह व्रत लगातार १२ अथवा १६ वर्षतक हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होनेके पश्चात इस व्रतका उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवनभर इस व्रतको कर सकती हैं। करवा चौथका व्रत हर साल महिलाओं द्वारा अपने पतियोंके लिए किया जाता हैं और यह न केवल एक त्योहार है, बल्कि यह पति-पत्नीके पवित्र रिश्तोंका पर्व है। कहनेको तो करवा चौथका त्योहार एक व्रत है लेकिन यह नारी शक्ति और उसकी क्षमताओंका सवश्रेष्ठ उदहारण हैं। क्योंकि नारी अपने दृढ़ संकल्पसे यमराजसे भी अपने पतिके प्राण ले आती हैं तो फिर वह क्या नहीं कर सकती हैं। आजके नये जमानेमें भी हमारे देशमें महिलाएं हर वर्ष करवा चौथका व्रत पहलेकी तरह पूरी निष्ठा एवं भावनासे मनाती है। सूर्योदयसे लेकर चंद्रोदयतक पत्नियां अपने पतिके प्रति पूरे प्रेम और सम्मानके साथ ये सभी रस्में निभाती हैं। यह त्योहार हर साल कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्थीको मनाया जाता है।

शास्त्रोंके अनुसार पतिकी दीर्घायु एवं अखण्ड सौभाग्यकी प्राप्तिके लिए इस दिन भालचन्द्र गणेश जीकी पूजा-अर्चना की जाती है। करवा चौथमें दिनभर उपवास रखकर रातमें चन्द्रमाको अर्ध्य देनेके उपरान्त ही भोजन करनेका विधान है। वर्तमान समयमें करवा चौथव्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवारमें प्रचलित प्रथाके अनुसार ही मनाती हैं। लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चन्द्रोदयकी प्रतीक्षा करती हैं। सायंकाल चंद्रमाके उदित हो जानेपर चंद्रमाका पूजन कर अर्ध्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों एवं पतिके माता-पिताको भोजन करायें। भोजनके पश्चात ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दें।

कार्तिक कृष्ण पक्षकी चन्द्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात् उस चतुर्थीकी रात्रिको जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन प्रात: स्नान करके अपने पतिकी आयु, आरोग्य, सौभाग्यका संकल्प लेकर दिनभर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमाका पूजन करें। शुद्ध घीमें आटेको सेंककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनायें। काली मिट्टीमें शक्करकी चासनी मिलाकर उस मिट्टीसे तैयार किये गये मिट्टीके अथवा तांबेके बने हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार १० अथवा १३ करवे रखें। करवा चौथके बारेमें व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वतपर गये। इधर द्रोपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलनेपर उन्होंने कृष्ण भगवानका ध्यान किया और अपनी चिन्ता व्यक्त की। कृष्ण भगवानने कहा बहना इसी तरहका प्रश्न एक बार माता पार्वतीने शंकरजीसे किया था। पूजन कर चंद्रमाको अर्ध्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। करवेका आपसमें आदान-प्रदान किया जाता है। जो आपसी प्रेमभावको बढ़ाता है। पूजन करनेके बाद महिलाएं अपने बड़ोंको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकरजीने माता पार्वतीको करवा चौथका व्रत बतलाया।

आधुनिक होते समाजमें भी महिलाएं अपने पतिकी दीर्घायुको लेकर सचेत रहती है। इसीलिए वह पतिकी लम्बी उम्रकी कामनाके साथ करवा चौथका व्रत रखना नहीं भूलती है। पत्नीका अपने पतिसे कितने भी गिले-शिकवे रहें हो परन्तु करवा चौथ आते-आते सब भूलकर वह एकाग्र चित्तसे अपने सुहागकी लम्बी उम्रकी कामनासे व्रत जरूर करती है। करवा चौथ शब्द करवा अर्थात् मिट्टीका बर्तन